भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2019

जिसका उत्तर 06.08.2025 को दिया जाना है

एनएच-716 के ओरमपाडु-रेणिगुंटा खंड को चार लेन का बनाया जाना

2019 श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-716 (कड़पा -रेणिगुंटा खंड का पैकेज - । और ॥) के लगभग 112 किलोमीटर लंबे ओरमपाडु-रेणिगुंटा खंड को चार लेन का बनाने के कार्य को 511 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2022 में मंजूरी दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ग) उपरोक्त परियोजना के पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है;

(घ) क्या परियोजना की लागत में कोई वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना में देरी के कारण क्या हैं और परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने दिसंबर 2022 में एनएच-716 (121.9 किमी लंबाई) के कडप्पा से रेणिगुंटा खंड के विकास कार्य को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल पूंजी लागत ₹ 3232.77 करोड़ है और इसे दो पैकेजों में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) से (ङ) दोनों पैकेज मार्च 2023 में सौंप दिए गए हैं, और रियायतग्राहियों के साथ रियायत करारों पर 28.01.2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। हालाँकि, वैधानिक मंजूरी जैसे वन विभाग से अनापत्ति और वन्यजीव/पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) से मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण अब तक कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। दोनों पैकेजों को शुरू होने की तारीख से 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व शर्तों के भाग के रूप में वित्तीय समापन प्राप्त करने पर कार्य शुरू होगा।

सभी विलंबित परियोजनाओं में लागत वृद्धि नहीं होती है। यदि देरी ठेकेदार के कारण नहीं होती है, तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित सूत्र के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत लग भी सकती है और नहीं भी, जो वास्तविक समापन पर निर्धारित मूल्य वृद्धि के अंतिम मूल्य और परियोजना अनुबंध/रियायती अवधि की समाप्ति के बाद बिलों के अंतिम निपटान पर निर्भर करता है। यदि देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो क्षतिपूर्ति लगाई जाती है और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगती है।

*****